केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा में 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने श्री श्री 1008 सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की समाधि के दर्शन किए।

महायज्ञ सामाजिक समरसता व पर्यावरण संरक्षण का अनूठा प्रयास है- अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक वर्ष से चल रहे महायज्ञ की महापूर्णाहुति में भाग लिया

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ब्रह्मलीन बाबा बालनाथ का जीवन मानव कल्याण के लिये समर्पित रहा तथा इस प्रकार के आयोजनों से उन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने का कार्य किया।

कोटपूतली-बहरोड़/जयपुर, 6 अप्रेल। रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा में 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत एक वर्ष से चल रहे 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ के माध्यम से बाबा बस्तीनाथ जी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का महान कार्य किया है। समाज को जोड़ने, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने और पर्यावरण की सेवा करने का यह अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अनेक भक्तों ने बाबा बालनाथ आश्रम में आकर नशामुक्ति की प्रतिज्ञा की और सामाजिक समरसता को बढ़ाने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा कि बाबा बालनाथ जी ने सत्य व तपस्या में विश्वास रखने, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाने, प्राकृतिक जीवन जीने तथा प्राणिमात्र की सेवा करने का संदेश दिया। उनकी इस विरासत को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'विकास के साथ विरासत' की भावना को साकार करते हुए राज्य सरकार भी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नित के लिए कार्य कर रही है।

शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का नेतृत्व और दूरदर्शिता देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्ध योगी ब्रह्मलीन बाबा बालनाथ जी महाराज का जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा तथा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने का कार्य किया।

इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने श्री श्री 1008 सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी के समाधि स्थल के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में एक वर्ष से अनवरत चल रहे 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ में पूर्णाहुति दी एवं आमजन की खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात् बाबा बालनाथ आश्रम में धूणी दर्शन कर पंचमुखी महाकाल मंदिर में आरती की। इस अवसर पर राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री विजय सिंह, सांसद राव राजेन्द्र सिंह, विधायक कुलदीप धनखड़, हंसराज पटेल, देवी सिंह शेखावत तथा श्री श्री 108 बाबा बस्तीनाथ जी महाराज सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

ट्रम्प की विवादास्पद नीतियों के खिलाफ अमेरिकी शहरों में विरोध प्रदर्शन

अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन व मानवाधिकार के मुद्दों पर अमेरिकी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे

- नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के संघ सहित 150 से अधिक समूहों के गठबंधन ने अमेरिका में 1400 से अधिक विरोध प्रदर्शन किये।

न्यूयॉर्क, 6 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा जनवरी से लागू की गई विवादास्पद नीतियों के खिलाफ गत दिवस अमेरिका के दर्जनों शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया।

अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन और मानवाधिकारों के मुद्दे पर ट्रम्प का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर उतरी।

नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों और सेवानिवृत्त सैनिकों के संघों सहित 150 से अधिक समूहों के गठबंधन द्वारा आयोजित इस समन्वित कदम के परिणामस्वरूप पूरे देश में 1,400 से अधिक विरोध प्रदर्शन हुए।

प्रदर्शनकारी, राज्य की राजधानियों, संघीय भवनों, कांग्रेस कार्यालयों, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन मुख्यालयों, नगर भवन और सार्वजनिक पार्क में एकत्रित हुए।

"हैंड्स ऑफ" के बैनर तले किए गए इस आंदोलन में कई तरह के विरोध प्रदर्शन और नारे शामिल थे, जैसे "कुलीनतंत्र का अंत करो", "क्रेजा को जीने दो" और "सामाजिक सुरक्षा बचाओ।" अभियान की आधिकारिक वेबसाइट 2025. पर एक लेख में कहा गया कि ट्रंप, मस्क और उनके अरबपति मित्र हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे मूल अधिकारों पर पूर्ण आक्रमण की योजना बना रहे हैं, जिसे हर कदम पर कांग्रेस द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

कुछ निर्वाचित अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हुए। बॉस्टन की मेयर मिशेल वू ने कहा, वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे और अन्य लोग ऐसी दुनिया में रहें जहां धमकी और भय ही सरकार का साधन हो और विविधता और शांति जैसे मूल्यों पर हमला हो।

आयोजकों के अनुसार, लगभग 600,000 लोगों ने "हैंड्स ऑफ" आंदोलन के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद से ट्रम्प प्रशासन को व्यापक नीतिगत परिवर्तनों के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें संघीय एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छंटनी, आप्रवासियों का निर्वासन, बजट में भारी कटौती और कई देशों पर टैरिफ लगाना शामिल है।

भाकपा ने वक्फ पर महागठबंधन की बैठक की मांग की

- पार्टी के बिहार राज्य सचिव ने सभी घटक दलों को पत्र भेजा।

पटना, 06 अप्रैल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने वक्फ कानून में संशोधन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए महागठबंधन की बैठक बुलाने के लिए सभी घटक दलों को पत्र लिखा है।

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त कर संशोधित वक्फ कानून बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए महागठबंधन के घटक दलों, राजद, कांग्रेस, माकपा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) को पत्र भेजा गया है। पांडेय ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा बनाए गए संशोधित वक्फ कानून पूरी तरह असंवैधानिक है क्योंकि यह वक्फ पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाकर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह कानून अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 26 की भी अवहेलना करता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधित कानून साम्प्रदायिक तनाव को भड़काने और आर्थिक संकट और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की रणनीति है।

चारधाम यात्रा मार्ग पर शुद्ध भोजन मिलेगा

देहरादून, 6 अप्रैल। चारधाम यात्रा मार्ग के होटल-ढाबों में इस बार तीर्थ यात्रियों को ना सिर्फ स्वच्छ और शुद्ध भोजन मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के अनुसार होटल कारोबारी भोजन में तेल, नमक और चीनी का प्रयोग भी कम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए भी तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही यात्रा मार्ग के होटल और खाद्य कारोबारियों के साथ व्यापक स्तर पर संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार सभी विभागों को 'हरित चारधाम यात्रा' थीम पर, यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने बताया कि इन कार्यशालाओं में होटल कारोबारियों से अपने भोजन में तेल, नमक और चीनी का उपयोग कम करने की अपील की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे

- राहुल गांधी से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व शिकुमार की मुलाकात के बाद हाईकमान ने निर्णय लिया
- पिछले कुछ समय से सिद्धारमैया के समर्थक, कुछ विधायक व मंत्री "एक व्यक्ति एक पद" के आधार पर शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मुहीम चला रहे थे।

बंगलूरू, 06 अप्रैल। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में सत्ता संघर्ष खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने रविवार को बताया कि, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर शीर्ष पद को लेकर कलह चल रही थी।

शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ पिछले गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली गए थे। जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवकुमार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मुहिम चल रही थी।सिद्धारमैया के खेमे के कई विधायक और मंत्री शिवकुमार को पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से हटने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी नीति, एक व्यक्ति, एक पद का पालन होना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि डीके शिवकुमार राज्य के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों पदों पर हैं, इसलिए पार्टी में उनके विरोधी यह तर्क दे रहे थे कि मंत्री पद का कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर उचित रूप से पार्टी प्रमुख का कर्तव्य नहीं निभा सकता है। हालांकि आलाकमान डीके शिवकुमार को इस पद से हटाने के मूड में नहीं है। क्योंकि डीके शिवकुमार ने विधानसभा चुनावों फिर लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाई थी और हालिया उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसलिए पार्टी उनके योगदान को देखते हुए, उन्हें उस पद से हटाना नहीं चाह रही है।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रामरथ (मोबाइल मेडिकल यूनिट) व 10 एम्बुलेन्स (108) का फ्लेग ऑफ करेंगे।

मुख्यमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य क्षय यूनिट को सम्मानित करते हुए टीबी चैंपियंस से संवाद भी करेंगे।

इस अवसर पर अधिकतम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत वाले उत्कृष्ट जिलों तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारिगणों/कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

चीन ने अमेरिका की नई मनमानी ''टैरिफ'' नीति के

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कवर नहीं थीं। अप्रैल 2023 में, डब्ल्यु.टी.ओ. विवाद पैनल ने भारत के खिलाफ निर्णय दिया। अनुपालन करने के बजाय, भारत ने अपील की- जिससे मामला प्रक्रिया संबंधी अनिश्चितता में चला गया, चूंकि अपीलीय निकाय में कोई सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्णय कानूनी रूप से निष्क्रिय बना हुआ है।

यह मामला वैश्विक व्यापार विवाद प्रणाली को प्रभावित करने वाली गहरी समस्या का प्रतीक है। देश अब भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और प्रारंभिक पैनल निर्णय जीत सकते हैं, लेकिन अपीलीय तंत्र के बिना, कोई बाध्यकारी समाधान नहीं होता।

हालांकि अमेरिका डब्ल्यू.टी.ओ. का सदस्य बना हुआ है और कुछ विवादों में भाग लेता है, लेकिन यह धीरे-धीरे अधिक चयनात्मक हो गया है। डब्ल्यू.टी.ओ. की कानूनी मशीनरी के प्रति अमेरिका का संदेह, विशेष रूप से चीन से जुड़े मामलों में, और मजबूत हो गया है। चूंकि रैसिप्रोकल टैरिफ प्रणाली को वॉशिंगटन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के संप्रभु हथिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी डब्ल्यू.टी.ओ. निर्णय संभवतः स्वागत योग्य नहीं होगा- या यहाँ तक कि उसे मान्यता भी नहीं दी जाएगी।

चीन के लिए, डब्ल्यू.टी.ओ. में दायर की गई शिकायत कई लक्ष्य साधती है। कानूनी रूप से, यह एकतरफा, संरक्षणवादी उपायों को चुनौती देती है। राजनीतिक रूप से, यह चीन को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के विखंडित होने के समय बहुपक्षीयता के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। यहां तक कि ऐसा निर्णय, जिसका पालन न हुआ हो तो भी उससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच चीन की विश्वसनीयता को मजबूत हो सकती है।

विस्तृत रूप से देखें तो यह मामला डब्ल्यू.टी.ओ. की प्रासंगिकता पर बहस को फिर से जागृत करता है। औपचारिक विवाद समाधान तंत्र प्रणाली में विश्वास के क्षीण होने के साथ, कई देश द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं- या पूरी तरह से कानूनी चैनलों को बायपास कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल वैश्विक व्यापार शासन को खंडित करती है बल्कि समान अवसर के मूल विचार की भी कमज़ोर करती है।

अगर डब्ल्यू.टी.ओ. चीन के पक्ष में निर्णय देता है, तो तत्काल परिणाम प्रक्रिया संबंधी पंगुता के कारण निर्णय सीमित हो सकता है। यह डब्ल्यू.टी.ओ. में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है, विशेष रूप सेइसके अपीलीय कार्य को बहाल करने के लिए और यह पुष्टि करता है कि बहुपक्षीय मंच अब भी महत्वपूर्ण हैं- भले ही वे विफल हो जाएं।

गठबंधनों और प्रतिद्वंदिताओं के बदलते युग में, वैश्विक व्यापार का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है कि क्या डब्ल्यू.टी.ओ. जैसी संस्थाओं को ठीक किया जा सकता है- या फिर क्या उनका अधिकार शून्य रहा जाएगा।

किसान नेता डल्लेवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, आंदोलन जारी है। दोबारा शुरू नहीं करने जा रहे। अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। किसी भी जत्थेबंदी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। विचार का सवाल है। कुछ विचारों को लेकर हम एकजुट हैं। कुछ मुद्दों पर अलग-अलग हैं।

उन्होंने कहा आप सरकार ने सुप्रीमो को बचाने के लिए हम पर बहुत बड़ा हमला किया है। आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा और अंत तक जारी रहेगा।

गौरतलब है कि लगभग 28 किसान संगठनों/यूनियनों ने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून व अन्य मांगों को लेकर फरवरी 2024 में नई दिल्ली कूच का आ ान किया था लेकिन हरियाणा सरकार के दिल्ली के रास्ते में पंजाब से लगती सीमाओं खनौरी व शंभू को सील किए जाने के कारण किसान दोनों सीमाओं पर धरने पर बैठ गए थे।

इस बीच डल्लेवाल ने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। डल्लेवाल के अनशन की गूंज उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय में भी सुनी गयी।

स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय माँगा

वे प्रस्तावित परिसीमन से जुड़ी तमिलनाडु की चिंताओं पर मोदी को ज्ञापन देना चाहते हैं

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिल जनता की आशंकाओं को दूर करने के लिये प्रधानमंत्री को संसद से प्रस्ताव पारित कराना चाहिये।

चेन्नई, 6 अप्रैल। तमिल में चल रहे भाषा एवं डीलिमिटेशन विवाद के बीच पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। हालांकि उनके कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम, एम के स्टालिन शामिल नहीं हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तावित डीलिमिटेशन (परिसीमन) प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। सीएम स्टालिन ने एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई योजनाओं की घोषणा की। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने प्रस्तावित डीलिमिटेशन से जुड़ी चिंताओं पर ज्ञापन सौंपने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमने परिसीमन पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। चूंकि मैं इस सरकारी समारोह में भाग ले रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें उनकी सभा में भाग लेने में असमर्थता से अवगत करा दिया है। मैंने इस कार्य के लिए अपने मंत्रियों, टी थेन्नारसु और राजा कन्नप्पन को भेजा है। इस सभा के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से डीलिमिटेशन की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।"

सीएम स्टालिन ने कहा, "आपको (मोदी को) यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में संसद में एक प्रस्ताव पारित हो। इससे (डीलिमिटेशन से) संसदीय सीट में कमी आएगी, इसलिए इसके बारे में पूछना हमारा अधिकार है। साथ ही यह हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है।" उन्होंने कहा, "पुडुचेरी को मिलाकर यहां 40 संसदीय सीट होंगी। लेकिन (केंद्र में) सत्तारूढ़ भाजपा सरकार परिसीमन के जरिये हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।" स्टालिन ने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक 22 मार्च को चेन्नई में आयोजित की गई थी जिसमें देशभर से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे।"

उन्होंने कहा," आप भी सफेद टी शर्ट पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए -सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए उसे हटाने के लिए। यहां रजिस्टर कर सफेद टी-शर्ट आंदोलन से जुड़िए। आइए, हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908